

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान

VOTE ON ACCOUNT

For

EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

फरवरी / February, 2019

2019-2020

लेखानुदान 2019-2020

संविधान के अनुच्छेद 116(1)(क) के अनुसरण में, पूरे वर्ष के लिए अनुदानों की मांगों पर विस्तृत-विचार तथा उन्हें पारित किए जाने तक, वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए लोक सभा से अनुरोध किया जा रहा है। इस विवरण में अप्रैल से जुलाई, 2019 के दौरान संभावित रूप से खर्च किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियों को दर्शाया गया है।

2. वर्ष 2019-20 के लिए कुल सकल व्यय ₹9743039.70 करोड़ होने का अनुमान है। इस आवश्यकता की तुलना में 'लेखानुदान' के अंतर्गत ₹3417295.38 करोड़ की राशि मांगी गई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

VOTE ON ACCOUNT 2019-2020

In pursuance of article 116(1) (a) of the Constitution, Lok Sabha is being requested to make a grant to cover expenditure for a part of the financial year, pending detailed consideration and passing of the Demands for Grants for the full year. This statement shows the sums required for meeting the expenditure, which is likely to be incurred during April to July, 2019.

2. Aggregate gross expenditure for 2019-20 is estimated at ₹9743039.70 crore. Against this requirement, the amount asked for 'on Account', is ₹3417295.38 crore as detailed below:

						रोड़ In ₹ crores)
		020 के लिए कुल सव		"लेर	बानुदान" में मांगी गई	धनराशि
	Total G	Gross Provision for 2	019-2020	Amo	unt asked for 'On A	Account'
	भारित	स्वीकृत	जोड़	भारित	स्वीकृत	जोड़
	Charged	Voted	Total	Charged	Voted	Total
राजस्व	816235.81	2297194.87	3113430.68	283162.53	885028.14	1168190.67
पूंजी	6003289.19	626319.83	6629609.02	2001101.96	248002.75	2249104.71
जोड़	6819525.00	2923514.70	9743039.70	2284264.49	1133030.89	3417295.38

- 3. मोटे तौर पर, प्रावधान में वर्ष 2019-20 की अनुदानों की मांगों में प्रदर्शित अनुमानित सकल व्यय के 1/3 भाग को दर्शाया गया है, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें व्यय को पूरे वर्ष के लिए एक समान रूप से विस्तारित नहीं किया गया है तथा जिसके लिए अप्रैल से जुलाई, 2019 के दौरान संभावित व्यय को पूरा करने के लिए अधिक प्रावधान की आवश्यकता है।
- 4. हालांकि, लेखानुदान में पूरे वर्ष के अनुमानित प्रावधान का 1/3 भाग शामिल किया गया है लेकिन उसमें शामिल प्रावधानों को किसी "नई सेवा" पर खर्च किए जाने का आशय नहीं है।
- 5. व्यय की उन मदों का ब्यौरा जिनके लिए लेखानुदान में कुल प्रावधान के 1/3 भाग से अधिक के लिए प्रावधान मांगा गया है, अतिरिक्त आवश्यकता के संक्षिप्त कारण निम्नलिखित हैं:
- मांग 4. परमाणु फर्जा विभाग- वर्ष 2019-20 की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए बढ़ी हुई ईंधन लागतों के कारण बकाया राशि का भुगतान करने के लिए राजस्व भाग में ₹240.58 करोड़ (स्वीकृत), संविदागत भुगतानों के लिए पूंजी भाग में ₹281.34 करोड़ (स्वीकृत) तथा न्यायालय की डिक्री के भुगतान के लिए पूंजी भाग में ₹6.67 करोड़ (भारित) का प्रावधान किया गया है।
- मांग 6. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग- असम गैस क्रेकर परियोजना से संबंधित वर्ष 2018-19 की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए राजस्व भाग में ₹66.67 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 7. उर्वरक विभाग- वर्ष 2018-19 की उर्वरक सब्सिडियों की संविदागत बाध्यताओं को पूरा करने/देयताओं को पूरा करने के लिए राजस्व भाग में ₹13907.63 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 9. नागर विमानन मंत्रालय- वर्ष 2018-19 की आस्थिगित प्रतिबद्धताओं संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए राजस्व भाग में ₹141.33 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

- 3. Broadly, the provision represents one-third of the estimated gross expenditure exhibited in the Demands for Grants, 2019-20, except in certain cases where the expenditure is not uniformly spread over the year and larger provision is required to meet the likely expenditure during April to July, 2019.
- 4. Although the Vote on Account includes one-third of the estimated provision for the whole year, the provisions therein are not intended to be used for expenditure on any "New Service".
- 5. Items of expenditure for which over and above one-third of the total provision has been sought in the Vote on Account, are mentioned below with brief reasons for the additional requirement:-
- **D. 4 Department of Atomic Energy** An additional provision of ₹240.58 crore (voted) in the Revenue Section for payment of arrears due to increased fuel costs, ₹281.34 crore (voted) in the Capital Section for contractual payments and ₹6.67 crore (charged) in the Capital Section towards payment of court decree has been provided to meet the additional requirement of 2019-20.
- D. 6 Department of Chemicals and Petrochemicals An additional provision of ₹66.67 crore (voted) in the Revenue Section has been provided to meet the additional requirement to meet committed liabilities of 2018-19 related to Assam Gas Cracker Project.
- **D. 7 Department of Fertilizers** An additional provision of ₹13907.63 crore (voted) in the Revenue Section has been provided to meet contractual obligations/carry over liabilities of fertiliser subsidies of 2018-19.
- **D. 9 Ministry of Civil Aviation** An additional provision of ₹141.33 crore (voted) in the Revenue Section has been provided to meet the additional requirement on deferred commitments of 2018-19.

- मांग 11. वाणिज्य विभाग- वर्ष 2019-20 की संविदागत और बाध्यकारी भुगतानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ब्याज समकरण योजना के अधीन एनईआईए और प्रतिपूर्ति के लिए राजस्व भाग में ₹762.03 करोड़ (स्वीकृत) तथा ईसीजीसी के लिए पूंजी भाग में ₹332.50 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 12. औद्योगिक नीति और संबर्द्धन विभाग जीएसटी रिफंड, अंतरण/माल भाड़ा सब्सिडी स्कीम और भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए राजस्व भाग में ₹ 1993.31 करोड़ (स्वीकृत) और पूंजी भाग में ₹ 500.10 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2019-20 के लिए सीमित हैं।
- मांग 15. उपभोक्ता मामले विभाग वर्ष 2019-20 के लिए देश में भारतीय मानक समय के प्रचार-प्रसार के लिए "विधिक मौसम विज्ञान विनियमन और प्रवर्तन का सुदृढ़ीकरण" नामक उप स्कीम की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए राजस्व भाग में ₹ 4.00 करोड़ (स्वीकृत) और पूंजी भाग में ₹ 16.00 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग वर्ष 2019-20 के लिए एनएफएसए आदि के तहत विकेंद्रीकृत खाद्य प्रापण के लिए एफसीआई और अन्य, राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी को पूरा करने के लिए राजस्व भाग में ₹65366.83 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 18. संस्कृति मंत्रालय वर्ष 2018-19 के आस्थिगित व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व भाग में ₹ 60.62 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 19. रक्षा मंत्रालय (विविध) सीएसडी भुगतानों, जहाजों, विमानों और बेड़े के अधिग्रहण तथा भूमि अधिग्रहण सिंहत सीएसओं की देयताओं के लिए राजस्व भाग में ₹ 5324.00 करोड़ (स्वीकृत) और पूंजी भाग में ₹877.48 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 20. रक्षा सेवाएं (राजस्व) वर्ष 2018-19 के आस्थिगत व्यय को पूरा करने के लिए और एचएएल, विदेशी विक्रेताओं, जहाजों की रीफिट/ मरम्मत, मशीनरी के कलपुर्जों, एविएशन स्टोरों, हथियारों के कलपुर्जों, पीओएल और मानक टेबल रेंट के भुगतानों सहित वर्ष 2019-20 की संविदागत बाध्यताओं को पूरा करने के लिए राजस्व भाग में ₹ 13833.73 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 21. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय वर्ष 2018-19 के आस्थिगित व्यय और 2019-20 की संविदात्मक बाध्यताओं, श्रीनगर में भूमि अधिग्रहण, डीआरडीओ को निधियां, रनवे रीसर्फेसिंग, मशीन और उपस्कर आदि के लिए व्यय को पूरा करने के लिए पूंजी भाग में ₹ 37423.98 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 23. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय वर्ष 2019-20 के संविदागत और बाध्यकारी भुगतानों को पूरा करने के लिए राजस्व भाग में ₹ 25.33 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 28. विदेश मंत्रालय वर्ष 2019-20 के बाध्यकारी/संविदागत भुगतानों और वर्ष 2018-19 के आस्थिगत व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व भाग में ₹ 2077.59 करोड़ (स्वीकृत) और पूंजी भाग में ₹ 392.33 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

- **D. 11 Department of Commerce** An additional provision of ₹762.03 crore (voted) in the Revenue Section for NEIA and reimbursement under Interest Equalisation Scheme and ₹332.50 crore (voted) in the Capital Section for ECGC has been provided to meet the additional requirement on contractual and obligatory payments of 2019-20.
- D. 12 Department of Industrial Policy & Promotion An additional provision of ₹1993.31 crore (voted) in the Revenue Section and ₹500.10 crore (voted) in the Capital Section has been provided to meet the additional requirement on GST refund, Transfer/Freight subsidy scheme and India International Convention and exhibition centre limited for the year 2019-20.
- D. 15 Department of Consumer Affairs An additional provision of ₹4.00 crore (voted) in the Revenue Section and ₹16.00 crore (voted) in the Capital Section has been provided to meet the additional requirement in the sub scheme 'Strengthening of Legal Metrology Regulation and Enforcement' for dissemination of Indian Standard Time in the country for the year 2019-20.
- D. 16 Department of Food and Public Distribution An additional provision of ₹65366.83 crore (voted) in the Revenue Section has been provided for meeting the Food subsidy to FCI and others, State Govts on decentralised food procurement under NFSA etc. for the year 2019-20.
- **D. 18 Ministry of Culture** An additional provision of ₹60.62 (voted) in the Revenue Section has been provided for meeting deferred expenditure of 2018-19.
- **D. 19 Ministry of Defence (Misc.)** An additional provision of ₹5324.00 crore (voted) in the Revenue Section and ₹877.48 crore (voted) in the Capital Section has been provided for CSD payments, carry over liabilities of CSO, including acquisition of ships, aircrafts & fleet and land acquisition.
- D. 20 Defence Services (Revenue) An additional provision of ₹13833.73 (voted) in the Revenue Section has been provided for meeting deferred expenditure of 2018-19 and contractual obligations of 2019-20 including payments to HAL, foreign vendors, refit/ repairs of ships, machinery spares, aviation stores, weapon spares, POL and arrears of Standard Table Rent.
- D. 21 Capital Outlay on Defence Services An additional provision of ₹37423.98 (voted) in the Capital Section has been provided for meeting deferred expenditure of 2018-19 and contractual obligations of 2019-20, land acquisition in Srinagar, funds to DRDO, runway resurfacing, machine & Equipment etc.
- **D. 23 Ministry of Development of North Eastern Region -** An additional provision of ₹25.33 (voted) in the Revenue Section has been provided for meeting contractual and obligatory payments of 2019-20.
- **D. 28 Ministry of External Affairs** An additional provision of ₹2077.59 crore (voted) in the Revenue Section and ₹392.33 crore (voted) in the Capital Section has been provided to meet obligatory/contractual payments for 2019-20 and deferred expenditure of 2018-19.

- मांग 29. आर्थिक कार्य विभाग वर्ष 2019-20 के लिए बाध्यकारी/ संविदागत भुगतानों को पूरा करने के लिए राजस्व भाग में ₹ 97.64 करोड़ (स्वीकृत) और पूंजी भाग में ₹ 20.95 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 31. वित्तीय सेवाएं विभागः वर्ष 2019-20 के लिए एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी का क्रय करने, आईआईएफसीएल को इक्विटी सहायता प्रदान करने तथा अन्य बाध्यकारी/संविदागत भुगतानों को पूरा करने के लिए राजस्व भाग में ₹83.33 करोड़ (स्वीकृत) और पूंजी भाग में ₹966.66 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 33. राजस्व विभागः संविदागत/बाध्यकारी भुगतानों के लिए राजस्व भाग में ₹196.82 (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 36. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखाविभागः वर्ष 2019-20 में वेतन के भुगतान के लिए राजस्व भाग में ₹341.45 करोड़ (स्वीकृत) और ₹10.17 करोड़ (भारित) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 39. पेंशनः वर्ष 2019-20 के मार्च माह के पेंशन के भुगतान के लिए राजस्व भाग में ₹4098 करोड़ (स्वीकृत) और ₹32 करोड़ (भारित) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 40. राज्यों को अंतरण : वर्ष 2019-20 में वेतन के भुगतान के लिए राजस्व भाग में ₹1666.67 करोड़ (स्वीकृत) और ₹16578.72 करोड़ (भारित) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागः वर्ष 2019-20 के बाध्यकारी भुगतान और वर्ष 2018-19 के आस्थिगित भुगतान के लिए राजस्व भाग में ₹2674.58 करोड़ (स्वीकृत) और पूंजी भाग में ₹448.33 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 44. भारी उद्योग विभाग : वर्ष 2019-20 के बाध्यकारी भुगतानों और वर्ष 2018-19 के आस्थगित भुगतानों के लिए राजस्व भाग में ₹271.69 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 46. गृह मंत्रालयः स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के भुगतान के लिए राजस्व भाग में ₹23.02 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 48. पुलिसः सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) जैसे बलों के लिए फ्लैट खरीदने और प्रशासनिक व्यय तथा वामपंथी अतिवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा के लिए राजस्व भाग में ₹14772.49 करोड़ (स्वीकृत) और पूंजी भाग में ₹2492.33 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 49. अंडमान और निकोबार द्वीप समूहः बिजली घरों और पोतों को चलाने के लिए एचएसडी आयल की खरीद करने के लिए राजस्व भाग में ₹100 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 58. उच्चतर शिक्षा विभागः उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण कार्यान्वित करने के खर्च को पूरा करने तथा एचईएफए को समान सहायता देने के लिए राजस्व

- **D. 29 Department of Economic Affairs** An additional provision of ₹97.64 crore (voted) in the Revenue Section and ₹20.95 crore (voted) in the Capital Section has been provided to meet obligatory/contractual payments for 2019-20.
- D. 31 Department of Financial Services An additional provision of ₹83.33 crore (voted) in the Revenue Section and ₹966.66 crore (voted) in the Capital Section has been provided for subscribing to Share capital of Exim Bank, Equity support to IIFCL and to meet other obligatory/contractual payments for 2019-20.
- **D. 33 Department of Revenue -** An additional provision of ₹196.82 crore (voted) in Revenue Section has been provided for contractual/obligatory payments.
- **D. 36 Indian Audit and Accounts Department** An additional provision of ₹341.45 crore (voted) and ₹10.17 crore (charged) in Revenue Section has been provided for payment of salaries for the year 2019-20.
- **D. 39 Pensions -** An additional provision of ₹4098 crore (voted) and ₹32 crore (charged) in Revenue Section has been provided for payment of pension for the month of March, 2019-20.
- **D. 40 Transfers to States** An additional provision of ₹1666.67 crore (voted) and ₹16578.72 crore (charged) in Revenue Section has been provided for payment of salaries has been provided for payment of salaries for the year 2019-20.
- **D. 42 Department of Health & Family Welfare** An additional provision of ₹2674.58 crore (Voted) in Revenue Section and ₹448.33 crore (Voted) in Capital Section has been provided for making obligatory payments of 2019-20 and deferred expenditure of 2018-19.
- **D. 44 Department of Heavy Industry** An additional provision of ₹271.69 crore (Voted) in Revenue Section has been provided for making obligatory payments of 2019-20 and deferred expenditure of 2018-19.
- **D. 46 Ministry of Home Affairs** An additional provision of ₹23.02 crore (Voted) in Revenue Section has been provided for payment of pension to Freedom Fighter Pension.
- D. 48 Police An additional provision of ₹14772.49 crore (Voted) in Revenue Section and ₹2492.33 crore (Voted) in Capital Section has been provided for making purchases of flats for Forces such as BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB and NSG and for administrative expenses and security in LWE affected States.
- **D. 49 Andaman & Nicobar Islands** An additional provision of ₹100 crore (Voted) in Revenue Section has been provided for procurement of HSD oil for power houses and for running vessels.
- D.58 Department of Higher Education An additional provision of ₹4276.00 crore (Voted) in Revenue Section ₹300.00 crore (voted) in the Capital Section has been provided to meet the

भाग में ₹4276.00 करोड़ (स्वीकृत) और पूंजी भाग में ₹300.00 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

- मांग 59. सूचना और प्रसारण मंत्रालय : मई, 2019 में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जुड़े व्यय के लिए राजस्व भाग में ₹2.00 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 61. विधि और न्याय : वर्ष 2019 में लोक सभा का आम चुनाव कराने के लिए राजस्व भाग में 666.66 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग 62. निर्वाचन आयोग : 'स्वीप' कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने तथा कार्यालय भवन के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण से जमीन के अधिग्रहण के लिए राजस्व भाग में ₹12.14 करोड़ (स्वीकृत) और पूंजी भाग में ₹16.67 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग सं 63. भारत का उच्चतम न्यायालयः वर्ष 2019-20 के संविदागत बाध्यकारी भुगतान करने के लिए राजस्व भाग में ₹5.00 करोड़ (भारित) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग सं. 67. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा : वर्ष 2018-19 के आस्थिगत व्यय के लिए राजस्व भाग नें ₹60.00 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग सं. 70. कार्मिक और प्रशिक्षण विभागः प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण और केंद्रीय सूचना आयोग में वेतन के भुगतान के लिए राजस्व भाग में ₹15.78 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग सं.73. योजना मंत्रालयः वर्ष 2018-19 के आस्थिगित व्यय के लिए राजस्व भाग में ₹124.55 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग सं.74. विद्युत मंत्रालयः वर्ष 2019-20 के बाध्यकारी भुगतान करने और 2018-19 के आस्थिगत व्यय के लिए राजस्व भाग में ₹1959.28 करोड़ (स्वीकृत) और पूंजी भाग में ₹369.76 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग सं.76. लोक सभाः वर्ष 2019-20 के संविदागत/बाध्यकारी भुगतान करने के लिए राजस्व भाग में ₹77.00 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग सं.80. रेल मंत्रालयः वर्ष 2019-20 के बाध्यकारी भुगतान करने और 2018-19 के आस्थिगित व्यय के लिए राजस्व भाग में ₹1940.05 करोड़ (स्वीकृत) और पूंजी भाग में ₹1987.86 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग सं.81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयः वर्ष 2019-20 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वचनबद्ध/बाध्यकारी भुगतान करने के लिए राजस्व भाग में ₹1831.83 करोड़ (स्वीकृत) और पूंजी भाग में ₹12002.50 करोड़ (स्वीकृत) तथा पूंजी भाग में ₹1.67 करोड़ (भारित) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मांग सं.82. ग्रामीण विकास विभागः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम स्कीम के तहत पहली किस्त जारी करने के लिए

- expenditure towards implementation of 10% EWS reservation in Higher Education Institutions and for providing equity support to HEFA
- **D. 59 Ministry of Information and Broadcasting -** An additional provision of ₹2.00 crore (voted) in the Revenue Section has been provided for expenditure related to National Film Award to be held in May, 2019.
- **D. 61 Law and Justice -** An additional provision of ₹666.66 crore (Voted) in Revenue Section has been provided for conduct of general elections to Lok Sabha in 2019.
- **D. 62 Election Commission** An additional provision of ₹12.14 crore (Voted) in Revenue Section and ₹16.67 crore (Voted) in Capital Section has been provided for Voters' awareness campaign under SVEEP programme and for acquisition of land from DDA for construction of office building.
- **D. 63 Supreme Court of India** An additional provision of ₹5.00 crore (Charged) in Revenue Section has been provided for making contractual/obligatory payments of 2019-20.
- **D. 67 Ministry of New and Renewable Energy** An additional provision of ₹60.00 crore (voted) in the Revenue Section has been provided for deferred expenditure of 2018-19.
- **D. 70 Department of Personnel & Training** An additional provision of ₹15.78 crore (voted) in the Revenue Section has been provided for payment of salaries in ARPG, CBI, CAT and CIC.
- **D. 73 Ministry of Planning -** An additional provision of ₹124.55 crore (voted) in the Revenue Section has been provided for deferred expenditure of 2018-19.
- **D. 74 Ministry of Power -** An additional provision of ₹1959.28 crore (Voted) in Revenue Section and ₹369.76 crore (Voted) in Capital Section has been provided for making obligatory payments of 2019-20 and deferred expenditure of 2018-19.
- **D. 76 Lok Sabha -** An additional provision of ₹77.00 crore (Voted) in Revenue Section has been provided for making contractual/ obligatory payments of 2019-20.
- **D. 80 Ministry of Railways -** An additional provision of ₹1940.05 crore (Voted) in Revenue Section and ₹1987.86 crore (Voted) in Capital Section has been provided for making obligatory payments of 2019-20 and deferred expenditure of 2018-19.
- D. 81 Ministry of Road Transport and Highways An additional provision of ₹1831.83 crore (Voted) in Revenue Section, ₹12002.50 crore (Voted) in Capital Section and ₹1.67 crore (charged) in Capital Section has been provided for making committed/ obligatory payments to NHAI in 2019-20.
- D. 82 Department of Rural Development An additional provision of ₹20000.00 crore (voted) in the Revenue Section has

राजस्व भाग में ₹20000.00 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

मांग सं.87. पोत परिवहन मंत्रालयः वर्ष 2019-20 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वचनबद्ध/बाध्यकारी भुगतान करने के लिए राजस्व भाग में ₹130.00 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

मांग सं.91. अंतरिक्ष विभागः वर्ष 2019-20 के बाध्यकारी भुगतान करने और 2018-19 के आस्थगित व्यय के लिए राजस्व भाग में ₹348.00 करोड़ (स्वीकृत) और पूंजी भाग में ₹522.00 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

मांग सं.92. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयः 7वीं आर्थिक जनगणना और अन्य सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्य आयोजित करने के लिए राजस्व भाग में ₹197.64 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

मांग सं.94. कपड़ा मंत्रालयः न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत भारतीय कपास निगम को हुई हानि की प्रतिपूर्ति और राज्य उपकरों का प्रेषण स्कीम के तहत राज्य के उपकरों के लिए राजस्व भाग में ₹1377.32 करोड़ (स्वीकृत) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

been provided for release of first instalment under the schemes Mahatma Gandhi NREGA.

- **D. 87 Ministry of Shipping** An additional provision of ₹130.00 crore (voted) in the Revenue Section has been provided for making committed/ obligatory payments to NHAI in 2019-20.
- **D. 91 Department of Space** An additional provision of ₹348.00 crore (voted) in the Revenue Section and ₹522.00 crore (voted) in the Capital Section has been provided for making obligatory payments of 2019-20 and deferred expenditure of 2018-19.

D. 92 Ministry of Statistics and Programme Implementation - An additional provision of ₹197.64 crore (Voted) in Revenue

Section has been provided for conducting field work of 7th Economic Census and other surveys.

D.94 Ministry of Textiles - An additional provision of ₹1377.32 crore (voted) in the Revenue Section has been provided to for reimbursement of losses to Cotton Corporation of India incurred under MSP and State levies under RoSL scheme.

लेखानुदान, 2019-2020 Vote on Account

31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के माह अप्रैल से जुलाई, 2019 के अपेक्षित लेखानुदान का अनुमानित व्यय Estimate of expenditure for which Vote on Account is required for the months of April to July, 2019 in the financial year ending on the 31st March, 2020

(करोड़ रुपये में) (In crores of Rupees) कुल मांग लेखे के लिए आवश्यक राशि **Total Demand** Amount required on Account Title of Demand or मांग या विनियोग का पूंजी Capital पूंजी Capital राजस्व Revenue राजस्व Revenue शीर्षक Appropriation स्वीकृत भारित स्वीकृत भारित स्वीकृत भारित स्वीकृत Charged Voted Charged Voted Charged Voted Charged Voted कृषि और कृषक कल्याण Ministry of Agriculture and मंत्रालय Farmers' Welfare कृषि, सहकारिता और Department of Agriculture, कृषक कल्याण विभाग Cooperation and Farmers' 129550.51 34.70 43183.50 11.57 कृषि अनुसंधान और Department of Agricultural शिक्षा विभाग Research and Education 8078.76 2692.92 पशु पालन, डेयरी कार्य Department of Animal तथा मात्स्यिकी विभाग Husbandry, Dairying and Fisheries 44.02 1155.46 14.67 3466.38 आणविक ऊर्जा विभाग **Department of Atomic Energy** 4. आणविक ऊर्जा Atomic Energy 1.00 14757.52 10.00 9399.37 5079.56 7.78 3320.68 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक Ministry of Ayurveda, Yoga and चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध Naturopathy, Unani, Siddha तथा होम्योपैथी and Homoeopathy (आयुष) मंत्रालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक 5 Ministry of Ayurveda, Yoga and चिकित्सा, युनानी, सिद्ध तथा Naturopathy, Unani, Siddha and होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय Homoeopathy 2245.55 0.21 748.52 0.07 रसायन और उर्वरक **Ministry of Chemicals** मंत्रालय and Fertilisers रसायन और पेट्रोरसायन Department of Chemicals and विभाग Petrochemicals 263.65 132.33 उर्वरक विभाग Department of Fertilisers 78514.95 0.05 35443.40 0.02 भेषज विभाग Department of Pharmaceuticals 235.45 0.06 78.48 0.02 ... नागर विमानन मंत्रालय Ministry of Civil Aviation नागर विमानन मंत्रालय Ministry of Civil Aviation 4474.99 25.01 1585.88 8.34 कोयला मंत्रालय Ministry of Coal 10. कोयला मंत्रालय 10 Ministry of Coal 822.05 274.02 वाणिज्य और उद्योग **Ministry of Commerce** मंत्रालरा and Industry 11. वाणिज्य विभाग Department of Commerce 5709.32 510.00 2409.88 391.67 12. औद्योगिक नीति तथा Deparment of Industrial Policy संवर्धन विभाग and Promotion 5001.79 672.72 2962.80 557.64 संचार मंत्रालय **Ministry of Communications** 13. डाक विभाग Department of Posts 0.80 30411.20 947.74 9786.22 315.91 14. दूरसंचार विभाग Department of Telecommunications 30693.64 9719.72 10231.21 3239.91 उपभोक्ता मामले, खाद्य और Ministry of Consumer Affairs, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय **Food and Public Distribution** 15. उपभोक्ता मामले विभाग 15 Department of Consumer 2240.32 51.50 749.44 27.83 16. खाद्य और सार्वजनिक 16 Department of Food and वितरण विभाग **Public Distribution** 106682.64 17108.71 190914.27 51326.12

				কুল	ा मांग		(₹करोड़ में) (In₹crores) लेखे के लिए आवश्यक राशि Amount required on Account				
					Demand						
मांग या विनियोग का	Title of Demand or		राजस्व Revenue पूंजी Ca		Capital	राजस्व Revenue पूंजी Ca			Capital		
शीर्षक	,	Appropriation	भारित Charged	स्वीकृत Voted	भारित Charge	स्वीकृत d Voted	भारित Charged	स्वीकृत I Voted	भारित Charge	स्वीकृत d Voted	
 कारपोरेट कार्य मंत्रालय	N#:	sistems of Components Affaire	Chargeu	voled	Charge	u voleu	Charged	ı voled	Charge	u voieu	
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय		nistry of Corporate Affairs Ministry of Corporate Affairs		527.63		51.00		175.88		17.00	
17. 47(11(0 47)4 17)(14	.,	William y or corporate randing	•••	027.00	•••	01.00		170.00	•••	17.00	
संस्कृति मंत्रालय	Mir	nistry of Culture									
18. संस्कृति मंत्रालय	18	Ministry of Culture		2874.31		168.04		998.52		56.01	
रक्षा मंत्रालय	Mir	nistry of Defence									
19. रक्षा मंत्रालय (विविध)	19	Ministry of Defence (Misc.)	0.76	30844.58	35.00	6946.82	0.25	13830.86	11.67	2900.59	
20. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	20	Defence Services (Revenue)	100.11	218682.60			33.37	82100.02			
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजी	21										
परिव्यय		Services			83.35	103296.99			27.78	59366.65	
22. रक्षा पेंशन	22	Defence Pensions	2.46	112077.11			0.82	37359.04	•••		
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	Mir	nistry of Development of									
ू मंत्रालय		North Eastern Region									
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	23	Ministry of Development of									
मंत्रालय		North Eastern Region		2325.90		734.10		792.19	•••	244.70	
पेयजल एवं स्वच्छता	Mir	nistry of Drinking Water									
मंत्रालय		and Sanitation									
24. पेयजल एवं स्वच्छता	24	Ministry of Drinking Water									
मंत्रालय		and Sanitation		25966.70				8655.57			
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	Mir	nistry of Earth Sciences									
25. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		Ministry of Earth Sciences		1788.05		118.00		596.02	•••	39.33	
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना	Mir	nistry of Electronics and									
प्रौद्योगिकी मंत्रालय	14111	Information Technology									
26. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना	26	Ministry of Electronics and									
प्रौद्योगिकी मंत्रालय		Information Technology		6072.00		348.00		2024.00		116.00	
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	Mir	nistry of Environment, Forests									
परिवर्तन मन्नालय 27. पर्यावरण, वन और जलवायु	27	and Climate Change Ministry of Environment, Fores	to								
परिवर्तन मंत्रालय	21	and Climate Change		3219.20		64.52		1073.07		21.51	
AICHCE TAICE		and omnate onange		0210.20	•••	04.02		1070.07	•••	21.01	
विदेश मंत्रालय		nistry of External Affairs									
28. विदेश मंत्रालय	28	Ministry of External Affairs	0.03	14686.75		1375.00	0.01	6280.48		719.89	
वित्त मंत्रालय	Mir	nistry of Finance									
29. आर्थिक कार्य विभाग	29	Department of Economic Affair	s	3061.18		17168.22		1085.49		5736.71	
30. व्यय विभाग	30	Department of Expenditure		400.55				133.52			
31. वित्तीय सेवाएं विभाग	31	Department of Financial Service	es	1305.16		3935.05		490.61		1956.12	
32. निवेश और लोक आस्ति	32	Department of Investment and									
प्रबंधन विभाग (दीपम)		Public Asset Management									
0		(DIPAM)		47.08				15.69			
33. राजस्व विभाग	33	Department of Revenue	0.02	203457.98	***	8.73	0.01	67950.54		2.91	
34. प्रत्यक्ष कर	34	Direct Taxes		7036.44		302.00		2345.48		100.67	
35. अप्रत्यक्ष कर	35	Indirect Taxes	0.50	7493.15		406.85	0.17	2497.72		135.62	
36. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	36	Indian Audit and Accounts	470.40	4000 70		40.00	05.51	1005.51		F 00	
लखा विभाग 37. ब्याज अदायगियां	27	Department	176.19			16.00	65.51	1835.54	•••	5.33	
37. ब्याज अदायागया 38. ऋण की अदायगी	37	•	677060.92		 983187.09	•••	225686.97		 994395.70	•••	
38. ऋण का अदायगा 39. पेंशन	38	Repayment of Debt Pensions	 380 10				1/8 03				
39. पशन 40. राज्यों को अंतरण	39 40			49184.90 32480.00	 19823.28			19126.97 11937.78	6607.76		
то. राज्या यम जरारण	+0	Transiers to States	101802.22	J240U.UU	13023.20		00018.08	11331.10	0001.10	•••	

				कुल ः	मांग		<i>(₹करोड़ में) (In₹crores)</i> लेखे के लिए आवश्यक राशि				
·· - 00->-				Total De	emand		Amount required on Account				
मांग या विनियोग का शीर्षक	Title of Demand or Appropriation		राजस्व	Revenue	पूजा 🕻	Capital	राजस्व ।	Revenue	पूजा С	apital	
	·		भारित Charged	स्वीकृत Voted	भारित Charged	स्वीकृत I Voted	भारित Charged	स्वीकृत Voted	भारित Charged	स्वीकृत Voted	
—————————— खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	Mir	nistry of Food Processing									
मंत्रालय		Industries									
41. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	41	Ministry of Food Processing									
मंत्रालय		Industries		1196.60				398.87	•••		
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	Mir	nistry of Health and									
मंत्रालय		Family Welfare									
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	42	Department of Health and									
विभाग		Family Welfare		87799.66		2890.20		30837.89		1241.29	
43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	43	Department of Health Research	•••	3374.65	•••		•••	1124.88			
भारी उद्योग और लोक	Mir	nistry of Heavy Industries and									
उद्यम मंत्रालय		Public Enterprises									
44 भारी उद्योग विभाग	44	Department of Heavy Industry		716.44		445.56		419.94		148.52	
45. लोक उद्यम विभाग	45	Department of Public Enterprises	s	22.64				7.55			
गृह मंत्रालय	Mir	nistry of Home Affairs									
46. गृह मंत्रालय	46	Ministry of Home Affairs	0.02	4615.02		280.77	0.01	1553.69		93.59	
47. मंत्रिमंडल	47	Cabinet		828.85				276.28			
48. पुलिस	48	Police	7.24	88725.49	6.33 1	10786.41	2.41	39423.49	2.11	5257.02	
49. अण्डमान और निकोबार	49	Andaman and Nicobar									
द्वीप समूह		Islands	0.01	4285.99		601.58		1495.33		200.53	
50. चंडीगढ़	50	Chandigarh	42.01	4309.48	25.00	376.63	14.00	1436.49	8.33	125.54	
51. दादरा और नगर हवेली	51	Dadra and Nagar Haveli	0.01	867.82		317.06		289.27		105.69	
52. दमन एवं दीव	52	Daman and Diu	0.02	1575.98		342.48	0.01	525.33		114.16	
53. लक्षद्वीप	53	Lakshadweep		1117.11		186.38		372.37		62.13	
54. दिल्ली को अंतरण	54	Transfers to Delhi		812.00		300.00		270.67		100.00	
55. पुडुचेरी को अंतरण	55	Transfers to Puducherry		1544.99		0.01		515.00			
आवासन और शहरी मामले	Mir	nistry of Housing and									
मंत्रालय		Urban Affairs									
56. आवासन और शहरी	56	Ministry of Housing and	0.1.0.1	05101.00	74.00			1000100	22.27	0.570.04	
मामले मंत्रालय		Urban Affairs	91.81	35421.29	71.92 ′	19472.42	30.60	12304.80	23.97	6570.21	
मानव संसाधन विकास	Mir	nistry of Human Resource									
मंत्रालय		Development									
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	5/	Department of School		07405 70				00.470.50			
58. उच्चतर शिक्षा विभाग		Education and Literacy		97435.76				32478.59			
58. उच्चतर शिक्षा विमाग	58	Department of Higher Education		51202.84		2120.00		15642.28		806.67	
	N.A.:	sisten, of Information and									
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	IVIII	nistry of Information and Broadcasting									
	F0	•									
59. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	59	Ministry of Information and Broadcasting		4361.67		13.54		1455.22		4.51	
श्रम और रोजगार मंत्रालय	N#:	pietry of Labour and									
या जार राणगार गंत्रासच	ivili	nistry of Labour and Employment									
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	60										
00. 21 T SITE (1911)	00	Employment		10403.83		30.26		3467.91		10.09	
विधि और न्याय मंत्रालय	Mir	nistry of Law and Justice									
61. विधि और न्याय	61			2920.11		135.00		1417.81		45.00	
62. निर्वाचन आयोग	62			261.68		25.00		95.32		19.45	
			•••			_0.00		33.02	•••		
63. विनियोग-भारत का	63	Appropriation - Supreme									

			कुल	मांग		<i>(₹करोड़ में) (In₹crores)</i> लेखे के लिए आवश्यक राशि				
			Total D				nt required		unt	
मांग या विनियोग का	Title of Demand or	राजस्व	राजस्व Revenue पूंजी Capital				राजस्व Revenue पूंजी Capital			
शीर्षक	Appropriation	भारित Charged	स्वीकृत Voted	भारित Charge	स्वीकृत d Voted	भारित Charged	स्वीकृत Voted	भारित Charged	स्वीकृत Voted	
————— सूक्ष्म, लघु और मध्यम	Ministry of Micro, Small and									
उद्यम मंत्रालय	Medium Enterprises									
64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम	64 Ministry of Micro, Small and									
उद्यम मंत्रालय	Medium Enterprises	•••	6984.27		27.02	•••	2169.72		9.01	
खान मंत्रालय	Ministry of Mines									
65. खान मंत्रालय	65 Ministry of Mines		1540.37		107.57		513.46		35.86	
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	Ministry of Minority Affairs									
	66 Ministry of Minority Affairs		4639.99		60.01		1546.66		20.00	
	, ,									
नवीन तथा नवीकरणीय	Ministry of New and									
ऊर्जा मंत्रालय	Renewable Energy									
67. नवीन तथा नवीकरणीय	67 Ministry of New and		5000.00		45.00		4770.04		45.00	
ऊर्जा मंत्रालय	Renewable Energy		5209.83		45.00		1776.61	•••	15.00	
पंचायती राज मंत्रालय	Ministry of Panchayati Raj									
68. पंचायती राज मंत्रालय	68 Ministry of Panchayati Raj		871.37				290.46			
संसदीय कार्य मंत्रालय	Ministry of Parliamentary Affair	'S								
69. संसदीय कार्य मंत्रालय	69 Ministry of Parliamentary Affa		19.38				6.46			
	Military of Bosses and Bullion									
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions									
70. कार्मिक, लोक शिकायत	70 Ministry of Personnel, Public									
और पेंशन मंत्रालय	Grievances and Pensions	3.79	1484.41	0.50	140.89	1.26	505.32	0.17	46.96	
71. केंद्रीय सतर्कता आयोग	71 Central Vigillance Commission	on 35.55				11.85				
पेट्रोलियम और प्राकृतिक	Ministry of Petroleum and									
गैस मंत्रालय	Natural Gas									
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक	72 Ministry of Petroleum and									
गैस मंत्रालय	Natural Gas	•••	42440.78		1667.31		31100.75	•••	541.75	
योजना मंत्रालय	Ministry of Planning									
73. योजना मंत्रालय	73 Ministry of Planning		362.71		0.69		203.94		0.23	
·										
विद्युत मंत्रालय 74. विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power 74 Ministry of Power		18774.62		3547.65		7564.39		1429.06	
	7.1 miniony of 1 one.	•••	1077 1.02	•••	0011.00	•••	7001.00	•••	1 120.00	
विनियोग-राष्ट्रपति, संसद,	The President, Parliament,									
संघ लोक सेवा आयोग	Union Public Service									
और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	Commission & the									
सावपालय	Secretariat of the Vice-President									
75. राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद	75 Appropriation - Staff,									
आवास और भत्ते	Household and Allowances									
	of the President	63.78				21.26	***			
76. लोक सभा	76 Lok Sabha	1.30	807.83			0.43	320.61			
77. राज्य सभा	77 Rajya Sabha	1.52	399.52			0.51	133.17			
78. उप-राष्ट्रपति का	78 Secretariat of the									
सचिवालय	Vice President		6.98				2.33			
79. विनियोग-संघ लोक सेवा	79 Appropriation - Union	000 45				00.40				
आयोग	Public Service Commission	298.45				99.48				
रेल मंत्रालय	Ministry of Railways									
80. रेल मंत्रालय	80 Ministry of Railways	463.28	272242.40	36.31	224626.60	154.43	92040.83	12.10	76200.77	

			कुल	 मांग		लेखे	के लिए आव	- ' '	₹crores
			पुरस Total De				d on Accou	unt	
मांग या विनियोग का	Title of Demand or	राजस्व Revenue पूंजी Capital			Capital	राजस्य Revenue पूंजी Capital			
शीर्षक	Appropriation	भारित Charged	स्वीकृत Voted	भारित Charged	स्वीकृत I Voted	भारित Charged	स्वीकृत Voted	भारित Charged	स्वीकृत Voted
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	Ministry of Road Transport								
मंत्रालय	and Highways								
31. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	81 Ministry of Road Transport								
मंत्रालय	and Highways		21686.98	10.00	142752.00		8450.21	4.45	55585.67
प्रामीण विकास मंत्रालय	Ministry of Rural Development								
32. ग्रामीण विकास विभाग	82 Department of Rural								
2. 20 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Development		191770.34		100.00		77256.78		33.33
33. भूमि संसाधन विभाग	83 Department of Land						200 0		00.00
6	Resources		2227.24				742.41		
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 34. विज्ञान और प्रौद्योगिकी	Ministry of Science and Technology 84 Department of Science								
विभाग विभाग	and Technology	0.02	5251.09		90.00	0.01	1750.36		30.00
अर्घ । 35. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	85 Department of Biotechnology		2580.34	•••			860.11	•••	
36. वैज्ञानिक और औद्योगिक	•	•••	2300.34				000.11		•••
अनुसंधान विभाग	86 Department of Scientific and Industrial Research		4886.24		9.65		1628.75		3.22
पोत परिवहन मंत्रालय	Ministry of Shipping								
37. पोत परिवहन मंत्रालय	87 Ministry of Shipping		1955.99		526.57		738.66		175.52
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship								
38. कौशल विकास और	88 Ministry of Skill Development								
उद्यमशीलता मंत्रालय	and Entrepreneurship		2926.11		63.10		975.37		21.03
प्तामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	Ministry of Social Justice and Empowerment								
39. सामाजिक न्याय और	89 Department of Social Justice								
अधिकारिता विभाग	and Empowerment		7524.99		275.01		2508.33		91.6
90. दिव्यांगजन सशक्तीकरण	90 Department of Empowerment								
विभाग	of Persons with Disabilities		1103.69		41.21		367.90		13.7
अंतरिक्ष विभाग	Department of Space								
91. अंतरिक्ष विभाग	91 Department of Space	0.60	5874.12	0.40	5663.14	0.20	2189.97	0.13	2235.28
	Military of Oracle Const.								
सांख्यिकी और कार्यक्रम	Ministry of Statistics and								
कार्यान्वयन मंत्रालय	Programme Implementation								
92. सांख्यिकी और कार्यक्रम	92 Ministry of Statistics and		5040.00		44.70		1070 51		4.0
कार्यान्वयन मंत्रालय	Programme Implementation	•••	5216.33	•••	14.73	•••	1870.54	•••	4.9
इस्पात मंत्रालय	Ministry of Steel								
93. इस्पात मंत्रालय	93 Ministry of Steel		241.29				80.43		
वस्त्र मंत्रालय	Ministry of Taytiles								
१ ५त्र मत्रालय १४. वस्त्र मंत्रालय	Ministry of Textiles		5800 57		20.04		2851.74		10.20
୬୫. ५୯୬ ୩୬୮୯୯	94 Ministry of Textiles		5800.57		30.91		2001./4		10.30
पर्यटन मंत्रालय	Ministry of Tourism								
95. पर्यटन मंत्रालय	95 Ministry of Tourism		2189.21	•••	0.01		729.74		
जनजातीय कार्य मंत्रालय	Ministry of Tribal Affairs								
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय									26.67

								(₹	₹करोड़ में) (Ir	(₹crores
				कुल	ा मांग	लेखे	लेखे के लिए आवश्यक राशि			
				Total [Demand	Amount required on Account				
मांग या विनियोग का शीर्षक	Title of Demand or Appropriation	राजस्व	Revenue	पूंजी	Capital	राजस्व Revenue		पूंजी Capital		
राविष्	,	Арргорпацоп	भारित	स्वीकृत	भारित	स्वीकृत	भारित	स्वीकृत	भारित	स्वीकृत
			Charged	Voted	Charge		Charged		Charge	d Voted
जल संसाधन, नदी विकास	Miı	nistry of Water Resources,								
और गंगा संरक्षण		River Development and								
मंत्रालय		Ganga Rejuvenation								
97. जल संसाधन, नदी	97	Ministry of Water Resources,								
विकास और गंगा संरक्षण		River Development and								
मंत्रालय		Ganga Rejuvenation	0.50	7678.22	0.01	421.89	0.17	2559.41		140.63
महिला और बाल	Mii	nistry of Women and Child								
विकास मंत्रालय	14111	Development								
98. महिला और बाल विकास	98	•								
मंत्रालय	30	Child Development		29664.89		0.01		9883.30		
गंत्रालय		Crilid Development	•••	29004.09		0.01		9005.50		
युवा मामले और खेल	Miı	nistry of Youth Affairs								
मंत्रालय		and Sports								
99. युवा मामले और खेल	99	Ministry of Youth Affairs								
मंत्रालय		and Sports		2181.90		35.02		727.30		11.67
जोड़-राजस्व/पूंजी		TOTAL REVENUE / CAPITAL	816235.81	2297194.87	6003289.19	626319.83	283162.54	885028.13	2001101.95	248002.76
जोड़ भारित		TOTAL CHARGED	6819525.00				2284264.49			
जोड़ स्वीकृत		TOTAL VOTED	2923514.70				1133030.89			
कुल जोड़		GRAND TOTAL	9743039.70				3417295.38			